दो महीने तक कच्ची चीनी का उत्पादन अनिवार्य हो: इंडस्ट्री

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खुले बाजार के लिए हर महीने चीनी जारी करने की व्यवस्था खत्म किए जाने की मांग उठी

[जयश्री भोसले | पुणे]

इंटरनेशनल मार्केट में सरप्लस सप्लाई होने की वजह से चीनी के दाम एक दशक के निचले स्तर पर आ गए हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे पेराई सीजन के शुरुआती दो महीनों के लिए रॉ शुगर के प्रॉडक्शन को जरूरी बनाने का राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बी बी ठोंबरे ने कहा, 'इंडियन व्हाइट शुगर की अभी डिमांड नहीं है इसलिए मिलों के लिए पेराई सीजन के पहले दो महीने में रॉ शुगर का प्रॉडक्शन जरूरी बनाने से इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी।'

यह अलग बात है कि इंडियन इंडस्ट्री 2017-18 में 20 लाख टन चीनी का निर्यात टारगेट हासिल करने में नाकामयाब रही थी क्योंकि उस दौरान चीनी का एक्सपोर्ट वित्तीय रूप से फायदेमंद नहीं था। अब उसने गन्ना किसानों के लिए इनसेंटिव बढ़ाए जाने की मांग की है।

- **इंडियन इंडस्ट्री** 2017-18 में 20 लाख टन चीनी का निर्यात टारगेट हासिल करने में नाकामयाब रही थी
- **इस दौरान** चीनी का एक्सपोर्ट वित्तीय रूप से फायदेमंद नहीं था
- **अगर इंडिया** से चीनी का एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है तो विदेशी बाजार में चीनी का भाव 10 सेंट प्रति पौंड पर आ सकता है

यूनियन कैबिनेट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर पिछले हफ्ते फैसला लेने वाली थी।

वह इस प्रपोजल पर अब इसी हफ्ते विचार कर सकती है। सरकार के फैसले पर इंटरनेशनल फ्यूचर्स पर दांव लगानेवाले निवेशकों की भी कड़ी नजर होगी। अगर इंडिया से चीनी का एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है तो विदेशी बाजार में चीनी का भाव 10 सेंट प्रति पौंड पर आ सकता है।

चीनी कारोबार से जुड़े कुछ एग्जिक्यूटिव्स ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खुले बाजार के लिए हर महीने चीनी जारी करने के मंथली शुगर रिलीज सिस्टम को खत्म किए जाने की भी मांग है।

शुगर ब्रोकर अभिजीत घोरपड़े कहते हैं, 'अगर रिलीज सिस्टम खत्म किए जाने पर तटीय राज्यों से लगभग 60-70 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट हो सकेगा। घरेलू बाजार की जरूरत उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें पूरी कर सकती हैं।'